भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1748
दिनांक 10 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

डेयरी फार्मिंग

1748. डॉ. शशि थरूरः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में डेयरी किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि उत्पादन लागत वर्तमान में प्रस्तावित दूध खरीद मूल्यों से अधिक है, किसानों को केवल 42-48 रुपये प्रति लीटर प्राप्त हो रहे हैं जबकि वास्तविक लागत लगभग 52 रुपये प्रति लीटर है, इससे डेयरी में पशुओं की संख्या घट रही है और किसानों इस कार्य को छोड़ रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने दूध की खरीद, प्रसंस्करण और ग्रामीण आय में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम सहित मौजूदा उन केन्द्रीय योजनाओं आकलन किया है जिन्होंने कृषि स्तर पर लाभकारी मूल्य या लागत सहायता में कोई सुधार नहीं किया है;

(ग) क्या योजना के डिजाइन और विशेष रूप से छोटे और सीमांत डेयरी उत्पादकों के लिए वास्तविक कृषि स्तर पर राहत के बीच कोई अंतर है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2026-27 में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि केन्द्रीय डेयरी विकास सहायता के परिणाम उत्पादकों के लिए व्यवहार्य हों और आर्थिक स्थिति, दूध की उचित कीमतें, आयात पर निर्भरता में कमी हो तथा ग्रामीण आजीविका को बनाए रखा जा सके?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिससे यह पता चले कि केरल में डेयरी किसानों को उत्पादन लागत के दूध की कीमतों से अधिक होने के कारण नुकसान हो रहा है या इस वजह से डेयरी पशुओं की संख्या में कमी आई है और किसानों ने यह काम छोड़ दिया है।

(ख) और (ग) DAHD, भारत सरकार दूध की खरीद और बिक्री की कीमतों को विनियमित नहीं करता है। सहकारी और निजी डेयरियां उत्पादन लागत, डेयरी उत्पादों के स्टॉक (जैसे, सफेद मक्खन, स्किम्ड मिल्क पाउडर), और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की मौजूदा स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर कीमतें तय करती हैं। हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार केरल सहित देशभर में सतत डेयरी विकास को बढ़ावा देने और छोटे तथा सीमांत डेयरी किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को संपूरित करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM).
ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

iii. डेयरी क्रियाकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO)
iv. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)
v. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)
vi. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)

ये योजनाएं बोवाइनों की दूध उत्पादकता को बेहतर बनाने, डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को पूरा करने, पशु आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने में सहायता करती हैं और डेयरी फार्मिंग से दूध उत्पादक की आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

*****